सूचना/दस्तावेज भेजने के लिए पत्र लिखे गए हैं।

इन मामलों पर कार्यवाही करने के लिए इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से एक अलग प्रभाग सृजित किया है।

विवरण

उपभोक्ता कल्याण निधि से सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य-वार प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं॰	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	153
2.	तमिलनाडु	113
3.	उत्तर प्रदेश	100
4.	मिजोरम	51
5.	राजस्थान	54
6.	दिल्ली	49
7.	उड़ीसा	51
8.	बिहार	26
9	पश्चिम बंगाल	19
10	गुजरात	22
11.	हरियाणा	16
12.	हिमाचल प्रदेश	16
13.	केरल	57
14.	कर्नाटक	23
15.	महाराष्ट्र	31
16.	जम्मू व कश्मीर	1
17.	चण्डीगढ़	7
18.	सिक्किम	2
19.	पंजाब	8
20.	त्रिपुरा	2
21.	मेघालय	2
22.	असम	3
23.	गोवा	2
24.	पाण्डिचेरी	1
25.	मध्य प्रदेश	8
	योग:	817

SC/ST in Super Bazar

1483. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the percentage of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes employees in the Super Bazar branch-wise;

(b) the percentage of posts actually held by SCs/STs and OBCs in Super Bazar as per 1991 census figures; and

(c) the measures taken to fill the backlog?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c) It has been reported by Super Bazar that it has a staff strength on 2222 employees out of which SC and ST employees account for 7.74% (172) and 1.53% (34) respectively. Super Bazar does not maintain branchwise details fo SC & ST employees. Super Bazar has no policy of reservation for other backward castes.

Super Bazar is a an autonomous Cooperative Society and it has its own personnel policy. Its policy provides for reservation fo 15% for S.C. and 7.5% for S.T. However, keeping inview the excess staff of Super Bazar, the management has put a ban for further recruitment of staff since 1989 except filling up some vacanies of technical nature.

Workers Staraned in UAE

1484. SHRI SIBTEY RAZI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to certain reports which appeared in a section of press on 14.7.95 indicating 67 Indian workers stranded in U.A.E.;

(b) whether 67 Indian technicians had come to UAE on a group visa to work for an Italian company;

(c) whether the Italian company for which they were granted group visa had already closed its office before arrival of Indian technicians in UAE capital;

(d) whether Government propose to take action against emigration officials of India who did not ensure smooth jobs guarantee before grant of emigration clearance;

(e) whether such fraudulent cases are on increase with connivance of emigration officials of India; and

(f) if so, remedial steps to be taken in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) Workers were granted ECNR endorsement by Office of the Protector of Emigrants, Cochin under simplified Emigration Procedure after obtaining the prescribed Affidavit from the Recruiting Agent, duly sworn in before the Judicial Magisterate. While granting ECNR enforsement in respect of six additional specified categories, the Protectors of Emigrants are not require to examine the terms and conditions of employment or insist for attested employment documents;

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1485. **श्री नरेश यादव:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्यन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के लिये निर्धारित एक करोड़ रुपए की धन राशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तो अब तक बिहार सहित किन-किन राज्यों के लिये राज्यों के लिये उक्त धनराशि जारी की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर अमंग): (क) और (ख) जी, नहीं। केवल दो नामित सदस्यों को छोड़ कर जिनसे विकल्पों की अभी प्रतीक्षा है, सरकार ने लोक सभा के सभी सांसदों को चालू वर्ष 1995-96 के लिये प्रथम किस्त के रूप में 50 लाख रु० की धनराशि जारी कर दी है। राज्य सभा के 22 सांसदों जिन्होंने जिले के लिये अपने विकल्पों को इंगित कर दिया है, के बारे में संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरे के अनुसार 19 जुलाई, 1995 तक राज्य सभा के प्रत्येक सांसद को 50 लाख रु० की प्रथम किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है **(नीचे देखिए)**

(ग) सरकार ने कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर शेष धनराशि को जारी करने का निर्णय लिया है।

विवरण

सांसद संसदीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन वर्ष 1995-96 के लिये आवंटित की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य	राज्य सभा सासंदो की संख्या जिनको 19.7.1995 तक धनराशि जारी की गई है
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	3
3.	बिहार	3
4.	गुजरात	2
5.	हिमाचल प्रदेश	1